



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या Appeal / File No	मूल आदेश नं / O/O No.	दिनांक / Date
	V2/4 & 5/GDM/2017 <i>6195 to 6198</i>	ST/419 & 420/2016-17	27.10.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-104-TO-105-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	06.11.2017	जारी करने की तारीख / Date of issue:	10.11.2017
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अथवा आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उप-आयुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर, राजकोट / जामनगर / गान्धीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से गुजित /
Arising out of above mentioned O/O issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-**
M/s. The Kutch Salt & Allied Inds. Ltd., "Rankers House" Plot No.18, Sector No. 8, Gandhidham-Kutch

इस आदेश(अपील) में व्यक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दावा कर सकता है/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, एवं सेवाकर अपील/सहायक निवारण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं 'फिन्स अधिनियम', 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है /
Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) विशेष न्यायालय से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील/सहायक निवारण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर.के. पारम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए /
The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Param, New Delhi in all matters relating to classification and valuation

(ii) उपरोक्त परिच्छेद (i)a) में बतलाए गए अपील के अलावा सभी अन्य अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील/सहायक निवारण (सिस्टम) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, द्वितीय तल, बहामुनी भवन, असावरी महमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए /
To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad 380016 in case of appeals other than as mentioned in para- (i)a) above

(iii) अपील/सहायक निवारण के समक्ष अपील दायर करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) विनियम, 2001 के नियम 6 के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में फॉर्म EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए / इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ उत्पाद शुल्क की शीट, धारा की रॉस और लगाया गया जुर्माना, तथा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कम से कम 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न की। निर्धारित शुल्क का अग्रिम, संबंधित अपील/सहायक निवारण की जगह के सहायक रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी सर्ववित्तिक बैंक के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए / संबंधित ड्राफ्ट का अग्रिम, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपील/सहायक निवारण की शाखा स्थित है / अथवा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आदेश-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /
The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(iv) अपील/सहायक निवारण के समक्ष अपील, फिन्स अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर विनियम, 1994 के नियम 9(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप में फॉर्म S.T.5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न की (इनमें से एक प्रति परामर्श होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहाँ उत्पाद शुल्क की शीट, धारा की रॉस और लगाया गया जुर्माना, तथा 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कम से कम 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न की। निर्धारित शुल्क का अग्रिम, संबंधित अपील/सहायक निवारण की जगह के सहायक रजिस्ट्रार के नाम में किसी भी सर्ववित्तिक बैंक के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए / संबंधित ड्राफ्ट का अग्रिम, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहाँ संबंधित अपील/सहायक निवारण की शाखा स्थित है / अथवा आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आदेश-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs 500/-

अपीलकर्ता (अपील)

(i) विल अपीलियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराएं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दायें की गयी अपील, सेवाकर विनियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित फॉर्म ST-7 में की जा सकती एवं उसके साथ अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्यापक (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करे (आपने दो एक प्रति प्रामाणिक होंगी चाहिए) और अपील द्वारा सहस्यक अपील अध्यापक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, को अपील न्यायाधिकरण को आवेदन दायें करने का निर्देश दायें जाने आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलियम (सेस्टेट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम 1994 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अपीलियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलियम परिकल्पना में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर भाग के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि इस कालेज चार्ज से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत 'मस किट या शुल्क' में विनय शामिल है।
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेस्टेट जमा की गई राशि
(iii) सेस्टेट जमा विनियमों के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्राधान्य विधियों (स. 2) अपीलियम 2014 के अंतर्गत में पूर्व किसी अपीलियम परिकारी के तहत विचारणीय स्थान पर अपील को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India.
इस आदेश की पुनरीक्षण प्रक्रिया विस्तृतिकृत मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अथवा तद्विषय, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन बुकाई, विला संसदीय, राजसव विभाग, चौथी मंजिर, जीवन दीप भवन, लॉट नम्बर, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid.

(i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहाँ नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से अथवा माल के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान या किसी भंडार गृह में या भंडार में माल के पारगमन के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / in case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India

(iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty

(iv) इतिनिर्धारित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इच्छा के लिए इस अपीलियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत सहाय की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अपीलियम (स. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई लचीले अथवा समावेषित पर या बंट से पारित किए गये हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998

(v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां फॉर्म संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) विनियमों, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट है, इस आदेश के लक्षण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपीलियम, 1994 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के संबंध में लॉर या TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ प्रिजनरिफिड निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। / जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 - का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त दरा से किया जाता है। इस लक्ष्य के होते हुए भी की विचार नहीं करते से बचने के लिए-व्यक्तिगत अपीलियम अथवा अपीलियम को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripps with if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.

(E) न्यायाधिकरण न्यायालय शुल्क अपीलियम 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थान आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क तिब्बित करना होगा। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-1 in terms of the Court Fee Act 1975, as amended.

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलियम (सेस्टेट) विनियमों, 1982 में उल्लिखित एवं अन्य संबंधित मामलों की उल्लिखित करने वाले विनियमों की और भी ध्यान संकल्पित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अपीलियम परिकारी को अपील दर्जित करने से संबंधित विवरण, विवरण और नवीकरण प्रावधानों के लिए, अपीलियम विनियमों के संदर्भ में www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

:: ORDER IN APPEAL ::

The appeals listed herein below have been filed by M/s. The Kutch Salt & Allied Industries Pvt. Ltd., "Maitri Bhavan", Plot No. 18, Sector-08, Gandhidham-Kutch (hereinafter referred to as "Appellant") against Orders-In-Original shown against each appeal no. (hereinafter referred to as "impugned orders") passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division, Gandhidham-Kutch (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority").

Sr. No.	Appeal File No.	Order-In-Original No. & Date	Period of Refund claim	Amount of refund claim rejected (in Rs.)
01.	V2/04/GDM /2017	ST/419/2016-17 27.10.2016	August, 2016	18,815/-
02.	V2/05/GDM /2017	ST/420/2016-17 27.10.2016	September, 2016	26,644/-

2. Since the issue involved is identical, all these appeals are being taken up together for decision.

3. The facts of the case are that the appellant filed refund claims under Notification No.41/2012-ST dated 29.06.2012 of service tax paid to various service providers for rendering taxable services in relation to export of goods for the period specified in the refund claims. The lower adjudicating authority vide impugned order rejected the rebate claim for the amount as shown in the above Table.

4. Being aggrieved with the impugned orders, the appellant preferred the appeals, *inter-alia*, on the grounds that the lower adjudicating authority has erred in law and also on facts in rejecting the refund of Swachh Bharat Cess (hereinafter referred to as "SBC") without assigning any cogent reason thereof. The refund claims of SBC have been rejected without affording any opportunity to the appellant to explain their case and thus violating the principles of natural justice.

5. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Manish H. Vora, Chartered Accountant, who reiterated grounds of Appeal and submitted that no opportunities of personal hearing have been given to them; that P.H. notices were not issued even though refunds of SBC were granted earlier; that P.H. notices were refunds of SBC have not been granted without any valid reasons.

5.1 The appellant submitted written submission wherein it has been interalia submitted that the only grievance of appellant is that the lower adjudicating authority has denied refund of SBC to the Appellant without affording

any opportunity/notice to the appellant to explain their case as to why such refund should not be denied to them. The lower authority has simply given go by to such fundamental Principle of Law and rejected the claim of the appellant by simply stating that "SBC is deductible from the claim" without assigning any reason as to why such claim is deductible thus violating the Principle of Natural Justice.

5.2 They have filed refund claim of Service Tax paid on the input service which they have utilized in export of goods as stipulated in Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012. The said Notification allows rebate of Service Tax paid on the taxable service received by the exporter of goods and utilized by them for export of goods. The enabling provisions for levy of SBC on services were incorporated under Section 119 of the Finance Act, 2015, under Chapter-V of the said Act.

5.3 The appellant referred Frequently Asked Question (FAQ) on SBC issued by CBEC wherein it has been clarified that SBC is not cess on service tax and all provisions relating to levy and collection of Service Tax as enumerated in Chapter-V of the Finance Act, 1994 and Rules made there under including those relating to exemption and refund from tax will be applicable to SBC also. Further CBEC prescribed an accounting code wherein refund of SBC should be accounted for. If there is no intention of allowing refund of SBC to the public at large, question of notifying accounting code for refund of SBC would not have arisen.

5.4 The appellant referred Notification Nos. 1/2016-ST to Notification No. 3/2016-ST dated 02.02.2016 and Notification No. 29/2016-ST and Notification No. 30/2016-ST both dated 26.05.2016 and submitted that these Notifications allowed SBC as rebate/refund to the exporter. It is submitted that vide Notification No. 1/2016, CBEC has increased the scheduled rate of tax refundable to the exporter due to increase in tax because of introduction of SBC whereas vide Notification No. 2/2016-ST & 3/2016/ST with respect to Notification No. 12/2013-ST dated 01.07.2013 and Notification No. 39/2012-ST dated 20.06.2012, refund of SBC is allowed to the exporter. It is also submitted that in their own case, the department itself has allowed the refund of SBC and therefore adopting the contrary stand in the case under consideration is not justifiable.

5.5 The appellant relied decision of Hon'ble High Court of Karnataka in the case of M/s. TVS Motors Ltd. wherein the Hon'ble High Court has held that rebate of automobile cess paid on motor vehicles exported out of India is refundable even though the same is not mentioned in the Notification No. 19/2004-CE(NT) and decision in the case of Shree Renuka Sugars Ltd. wherein the Hon'ble court has held that the cess which is levied on production of sugar is

nothing but a duty of excise and as per Rule-3 of the Cenvat Credit Rules-2014, credit of such duty as excise are available to the appellant. The same analogy would apply to the case of SBC and appellant is eligible and entitled for refund of SBC as service tax paid on service received which were utilized for export of goods.

FINDINGS:

6. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned orders, appeal memorandums and the submissions of the appellant. The issue to be decided in the present case is as to whether the appellant is entitled for rebate of SBC paid on services used for export of goods under Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012 or not.

7. The appellant has contended that the refund claims were rejected without assigning any cogent reasons, without issuance of SCN and without affording any opportunity to the appellant to explain their case and thereby impugned orders have violated the principles of natural justice. I find force in the arguments made by the appellant. I find that the refund claims were decided by the lower adjudicating authority without issuance of SCN and even without granting opportunities of personal hearing to the appellant. It is settled position of law that the refund claims should not be rejected without issuance of SCN demonstrating reasons for denial of refund claims and without affording sufficient opportunities to explain their case. Hence, I find that the impugned orders are not sustainable at all, the same being non-speaking orders as far as rejecting refund claims of SBC is concerned.

7.1 In view of the above facts, I am of the considered view that the impugned orders need to be set aside and the matter needs to be remanded back to the lower adjudicating authority to pass speaking and reasoned orders offering fair opportunities to the appellant.

8. I find that the Commissioner (Appeals) has power to remand appeals as decided by the Hon'ble CESTAT in the case of CCE, Meerut Vs. Singh Alloys (P) Ltd. reported as 2012(284) ELT 97 (Tri-Del). I also rely upon decision of the Hon'ble CESTAT in the case of CCE, Meerut-II Vs. Honda Seil Power Products Ltd. reported in 2013 (287) ELT 353 (Tri-Del) wherein it has been held that Commissioner (Appeals) has inherent power to remand a case under the provisions of Section 35A of the Act. The Hon'ble Gujarat High Court in Tax Appeal No. 276 of 2014 in respect of Associated Hotels Ltd. has also held that even after the amendment w.e.f. 11.05.2011 in Section 35A (3) of the Central Excise Act, 1944, the Commissioner (Appeals) would retain the power to remand.

9. In view of above, I set aside the impugned orders to the extent of rejection of refund of SBC and allow the appeals by way of remand with direction to the jurisdictional adjudicating authority to pass speaking and reasoned order within three (03) months of the receipt of this order giving fair and reasonable opportunities to the appellant to submit their written submissions.

९.१ अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलस का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
9.1. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

(Handwritten Signature)
6/11/2022
(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By Regd. Post AD

To,

M/s. The Kutch Salt & Allied Industries Pvt. Ltd.,
"Maitri Bhavan", Plot No. 18, Sector-08,
Gandhidham-Kutch

मे. ध कच्छ सोल्ट & एलेड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड,
"मैत्री भवन", प्लॉट न. १८, सेक्टर - ०८,
गांधीधाम - कच्छ

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise, Kutch Commissionerate, Gandhidham
- 3) The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Division, Gandhidham
- 4) F. No. V2/05/GDM/2017
- 5) Guard File.